www.sanjanabharati.com

दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित

facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 राजनीतिक दलों को कार्यस्थल पर पॉश एक्ट...

3 पुलिस ने रतनपुर गांव से जाली नोट के साथ दो...

4 किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को...

वर्ष: 9 | अंक: 327 | दिल्ली, शनिवार, 20 सितम्बर 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

करण जौहर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत

नई दिल्ली (एजेन्सी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और फिल्म निर्माता करण जौहर को उनके व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में राहत प्रदान की है। न्यायालय ने आदेश दिया कि उनके विरुद्ध बनाए गए विवादास्पद वीडियो, मीम्स और सोशल मीडिया पोस्ट हटाए जाएँ। आदेश में ऐसी सभी 'अपमानजनक सामग्री' को तत्काल हटाने का निर्देश दिया गया है। लाइव लॉ के अनुसार, न्यायालय ने कहा, "प्रथम दृष्टया मूल्यांकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 7, 14 और 15 के प्लेटफार्मों पर उपलब्ध वीडियो, मीम्स और सोशल मीडिया पोस्ट में अपमानजनक और अपवित्र शब्दों के साथ-साथ ऐसे संकेत भी हैं जो आपत्तिजनक प्रतीत होते हैं। उक्त सामग्री वादी की प्रतिष्ठा और साख को धूमिल करती है, जिससे उसकी ब्रांड वैल्यू प्रभावित होती है। वादी प्रथम दृष्टया ऐसे नकारात्मक उपयोग के विरुद्ध अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है।

नीतीश ने हॉकी चैंपियंस को किया सम्मानित

पटना (एजेन्सी)। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद' में आयोजित सम्मान समारोह में हीरो एशिया कप, 2025 की विजेता की विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ियों, मुख्य प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षकों को 10-10 लाख रुपये एवं सपोर्ट स्टाफ को 5-5 लाख रुपये की सम्मान राशि एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान श्री हरमनप्रीत सिंह को खिलाड़ियों तथा सहयोगी स्टाफ के लिये कुल 2 करोड़ 50 लाख रुपये का सांकेतिक चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों, मुख्य प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, सपोर्ट स्टाफ को जीत की बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों के साथ ग्रुप तस्वीर भी खिंचवाई।

पीयूष गोयल ने अबू धाबी में बढ़ाई भारत की आर्थिक कूटनीति

नई दिल्ली (एजेन्सी)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अबू धाबी के उप शासक शेख तहनून बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की और उभरती प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे में निवेश और ऊर्जा सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। अबू धाबी के उप शासक द्वारा एक्स पर लिखे गए एक पोस्ट के अनुसार, बैठक में भारत-यूएई रणनीतिक साझेदारी की बढ़ती गहराई को रेखांकित किया गया, जिसमें दोनों पक्षों ने नवाचार आधारित सहयोग और मजबूत निवेश संबंधों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। शेख तहनून ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैंने भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, महामहिम पीयूष गोयल से मुलाकात की, जहाँ हमने नवीनतम आर्थिक और तकनीकी रुझानों, उत्पादकता बढ़ाने और विकास को गति देने में एआई की भूमिका, साथ ही बुनियादी ढाँचे में निवेश और ऊर्जा सुरक्षा के अवसरों पर चर्चा की। हमने नवाचार, बुनियादी ढाँचे में निवेश और प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग के माध्यम से यूएई-भारत साझेदारी को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

दिल्ली ने रचा इतिहास

50 साल बाद आया नया ड्रेनेज मास्टर प्लान, अगले 30 साल तक शहर को बाढ़ मुक्त रखने की तैयारी

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने नया ड्रेनेज मास्टर प्लान पेश किया, जो राष्ट्रीय राजधानी में बार-बार होने वाली शहरी बाढ़ और जलजमाव की समस्याओं को अगले 30 वर्षों तक हल करने के लिए एक ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट है। इसका शुभारंभ NDMC कन्वेंशन सेंटर में सेवा पखवाड़ा उत्सव (17 सितंबर-2 अक्टूबर) के तहत किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर मनाया जा रहा है।

इस अवसर पर माननीय आवास एवं शहरी कार्य और पावर मंत्री श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और PWD एवं I&FC मंत्री प्रवेश साहिब सिंह उपस्थित थे, जिन्होंने नजफगढ़, बालापुला और ट्रांस यमुना बेसिन के लिए तैयार तीन अलग-अलग मास्टर योजनाओं का संयुक्त रूप से अनावरण किया। यह योजना अगले तीन दशकों के लिए दिल्ली के ड्रेनेज ढांचे को भविष्य-सक्षम बनाने का लक्ष्य रखती है।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, जल संबंधी मुद्दे हमारे शहर की भलाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें पीने का पानी, वर्षा जल निकासी और सीवेज सिस्टम शामिल हैं। दिल्ली का नया ड्रेनेज मास्टर प्लान इस प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि हम इन महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए कटिबद्ध हैं। वर्षों की परिश्रमपूर्वक परामर्श, डेटा संग्रह और अध्ययन के बाद तैयार की गई यह व्यापक योजना दिल्ली की ड्रेनेज आवश्यकताओं के लिए रोडमैप प्रदान करेगी, जिससे जलजमाव से राहत मिलेगी और शहर को ड्रेनेज संबंधी चुनौतियों से सुरक्षित रखा जाएगा। इस योजना के तहत शहरी बाढ़ से निपटना, सतही जल भंडारण में सुधार, जल बहाव कम करना और मुख्य स्टॉर्मवॉटर चैनलों को अपग्रेड करना शामिल है, जिससे दिल्लीवासियों का जीवन स्तर सुधरेगा, मंत्री ने जोड़ा।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की अपनी प्रारंभिक समीक्षा साझा करते हुए बरापुल्ला नाला, कुशक ड्रेन, मिंटो ब्रिज और ITO ब्रिज के अपने व्यक्तिगत निरीक्षण का उदहारण दिया। उन्होंने गर्व से कहा कि इस साल पहली बार मिंटो ब्रिज और ITO जैसी जगहों पर गंभीर जलजमाव नहीं देखा गया, जो पहले एक आम समस्या थी।

मुख्यमंत्री ने एक प्रमुख पहल की घोषणा करते हुए कहा कि 30 सितंबर को सेवा पखवाड़ा उत्सव के हिस्से के रूप में 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें यमुना पुनर्जीवन योजना भी शामिल है। यह योजना चरणबद्ध और संरचित तरीके से लागू की जाएगी।

दिल्ली सरकार के आवश्यक प्रयासों को रेखांकित करते हुए, PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा, जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने तुरंत दिल्ली में जलजमाव की समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठाए। हमने शहर के मुख्य जलजमाव बिंदुओं का दौरा किया और ठोस कदम उठाए। हमारे विभागों ने 20 लाख मीट्रिक टन की गाद निकालकर सी&डी प्लांटों में भेजी। उन्होंने आगे कहा, मुझे गर्व है कि पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक बारिश होने के बावजूद, दिल्ली में कोई गंभीर बाढ़ नहीं आई। हमारा एकीकृत ड्रेनेज मास्टर प्लान यह सुनिश्चित करने का रोडमैप है कि दिल्ली बाढ़ मुक्त रहे और हमारे नागरिक बिना जलजमाव की चिंता किए जीवन जी सकें। यह ड्रेनेज मास्टर प्लान केवल कागज पर योजना नहीं है; यह गारंटी है कि दिल्ली आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत और बाढ़ मुक्त रहेगी। और जल्द ही, हम दिल्ली के लिए सीवर मास्टर प्लान और जल मास्टर प्लान भी लाएंगे, ताकि इस ड्रेनेज ढांचे को पूरा किया जा सके और शहर का जल प्रबंधन पूरी तरह से भविष्य-सक्षम बनाया जा सके।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दिल्ली की पिछली व्यापक ड्रेनेज योजना 1976 में तैयार की गई थी, जब शहर की आबादी केवल 60 लाख थी। आज, जब आबादी लगभग 2.5 करोड़ के करीब है और शहरीकरण तेज है, यह नई योजना अत्यंत आवश्यक हो गई है।

PWD ने आठ नागरिक एजेंसियों के परामर्श से इस योजना को तैयार किया, जिसमें सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, MCD, DDA, NHAI, DJB और NDMC शामिल हैं। नया ड्रेनेज मास्टर प्लान पूरे 18,958 किमी के ड्रेनेज नेटवर्क को कवर करता है।

योगी आदित्यनाथ का दावा: किसानों को मिल रहा उपज का पूरा मूल्य

(एजेन्सी)।

उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव के दौरान किसानों के कल्याण में सुधार पर प्रकाश डाला। अपने भाषण में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को अब उनकी उपज का भुगतान मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी विभिन्न सामाजिक बीमा योजनाओं के माध्यम से किसान अपने ऋण चुकाने में सक्षम हो रहे हैं। आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, सरकार द्वारा दिए गए 6,000 रुपये के माध्यम से 11 करोड़ किसान साहूकारों के चंगुल से मुक्त हो गए हैं।" उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मिशन रोजगार जैसी स्टार्टअप योजनाओं ने युवाओं के जीवन को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को उनकी सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ने का काम किया गया है। मिशन रोजगार, स्टार्टअप और स्टैंडअप योजनाओं ने युवाओं के जीवन को बदल दिया है... आज, भारतीय युवा नौकरी चाहने वाला नहीं है; वह नौकरी देने वाला बनने की क्षमता रखता है।

रेखा गुप्ता के कुशल नेतृत्व में दिल्ली सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों को और अधिक उन्नत कर रही है: दिल्ली के शिक्षा मंत्री

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के 38वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर दिल्ली के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री, रविंदर सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेजेज प्रो. बलराम ने की।

CBS देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान शहीद श्री राजगुरु के नाम पर स्थापित है।

कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों, छात्रों आदि को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र जीवन को याद करते हुए कहा कि उस दौर और आज के शैक्षिक माहौल में बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा की हमारे समय में न वाई-फाई था न स्मार्टफोन और न ही ऐसे भव्य ऑडिटोरियम। हमारी सोशल मीडिया सिर्फ कॉलेज के नोटिस बोर्ड थे और हमारे स्टेटस अपडेट लेक्चर के दौरान हाथ से लिखी पर्चियाँ होती थीं। छात्रों को जो विश्व स्तरीय सुविधाएँ मिल रही हैं जो पिछले 11 वर्षों में देश की प्रगति का प्रतीक है। श्री सूद ने कॉलेज को लगातार छह वर्षों तक BBA स्ट्रीम में भारत का No.1 अंडरग्रेजुएट कॉलेज चुने जाने पर बधाई दी और इसे CBS की परंपरा व निरंतरता का प्रमाण बताया। उन्होंने कॉलेज की शानदार प्लेसमेंट की भी सराहना की। कॉलेज के छात्रों को 2024-25 में 28 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक के पैकेज मिले और औसत पैकेज 11.5 लाख रुपये रहा। BCG, McKinsey, Deutsche Bank और DE Shaw जैसी कंपनियों ने छात्रों को नियुक्त किया। 70 से अधिक छात्रों ने विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाया जिससे सिद्ध होता है कि CBS भारत की युवा प्रतिभाओं के लिए लॉन्चपैड है। शिक्षा मंत्री ने CBS के Innovation and Incubation Foundation द्वारा बनाए गए उद्यमशील माहौल का जिक्र करते हुए कहा की कॉलेज ने 11 स्टार्टअप का मार्गदर्शन कर उल्लेखनीय राजस्व प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि CBS केवल नौकरियाँ देने का स्थान नहीं है, बल्कि नौकरियाँ सृजन करने का केंद्र भी है। उन्होंने यह भी कहा कि CBS ऐसे नेतृत्व को तैयार कर रहा है जो डेटा एनालिटिक्स, फिनटेक, वेल्थ प्लानिंग और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत-2047 की यात्रा का मार्ग प्रशस्त करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्धरण देते हुए उन्होंने छात्रों को याद दिलाया की भारत के पास लाखों समस्याएँ हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास अरबों दिमाग भी हैं। और इनमें से कई दिमाग CBS जैसे संस्थानों में पोषित हो रहे हैं।

स्वैच्छिक रक्तदान के क्षेत्र में हरियाणा बना रहा अपनी अलग पहचान: सीएम नायब सिंह सैनी

पिछले 11 वर्षों में हरियाणा प्रदेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में दर्ज किए बड़े सुधार

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने, स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने और ब्लड बैंक सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि हरियाणा में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेवाओं का उच्चतम मानक बना रहे और प्रत्येक नागरिक को समय पर सुरक्षित रक्त उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को गुरुग्राम में आयोजित इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनो हेमेटोलॉजी (आईएसबीटीआई) के 50वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन, 'स्वर्ण जयंती ट्रांसकॉन 2025' के उद्घाटन समारोह को बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में सहकारिता, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा, पटौदी की विधायक श्रीमती बिमला चौधरी, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर तथा गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में हरियाणा में कुल 149 ब्लड सेंटर कार्यरत हैं जिनके माध्यम से इस वर्ष 3 लाख 30 हजार यूनिट्स ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि निर्धारित लक्ष्यों के तहत अब तक 2 लाख 22 हजार 433 यूनिट ब्लड एकत्रित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सैनिकों, किसानों और युवाओं की भूमि है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रदेश ने आज वह मुकाम हासिल कर लिया है, जहाँ हरियाणा एक ओर औद्योगिक पहचान के रूप में देशभर में अग्रणी है तो दूसरी ओर स्वैच्छिक रक्तदान के क्षेत्र में भी अब हरियाणा अपनी अलग पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है। पिछले 11 वर्षों में प्रदेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार दर्ज किए हैं। उन्होंने बताया कि जहाँ पहले 30 बेड के अस्पताल हुआ करते थे, वहाँ अब 100 बेड की सुविधा उपलब्ध है। इसी प्रकार 100 बेड वाले अस्पतालों को 200 बेड और 200 बेड वाले अस्पतालों को 400 बेड तक विस्तार दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार धरातल पर गंभीरता से कार्य कर रही है ताकि प्रदेश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जहाँ हरियाणा में प्रतिवर्ष केवल 700 डॉक्टर ही तैयार होते थे, वहीं आज यह संख्या बढ़कर 2600 प्रति वर्ष हो गई है। सरकार का लक्ष्य इस संख्या को बढ़ाकर वर्ष 2029 तक 3400 सीटें प्रतिवर्ष तक पहुँचाने का है। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि युवाओं को बेहतर अवसर मिलें और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयां प्राप्त हों।

सीएम की ओर से आढ़तियों की मांगों को भारत सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठाने का भरोसा

खरीद प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने आढ़तियों के हितों की रक्षा के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए आज कहा कि राज्य सरकार उनकी जायज मांगों को भारत सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठाएगी।

यहां आढ़तियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उनकी जायज मांगों को पूरी गंभीरता के साथ हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आढ़तियों की अधिकांश मांगें केंद्र सरकार के दायरे में आती हैं और केंद्र सरकार द्वारा इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भगवंत सिंह मान ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार आढ़तियों की आवाज बनेगी और उनके मुद्दों को केंद्र के समक्ष जोरदार ढंग से उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आढ़तियों के कमीशन में वृद्धि का मामला पहले ही केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जा चुका है। उन्होंने आढ़तियों की भूमिका को महत्व न देने के लिए केंद्र की आलोचना की और कहा कि आढ़तिए खरीद कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भगवंत सिंह मान ने आढ़तियों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें पूरी खरीद प्रक्रिया का आधार बताया।

आढ़तियों के महत्व को उजागर करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि आढ़तिए किसानों के बिना वेतन वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो फसल उत्पादन और वित्तीय लेन-देन का विस्तृत रिकॉर्ड रखते हैं। अपने पैतृक जिले संगरूर में आढ़तियों के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभवों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वे खरीद प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की ओर से अनाज खरीदती है और सावन मंडीकरण सीजन 2025-26 के दौरान सुचारू और निर्बाध खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हाल ही में आई बाढ़ के कारण हुए भयानक नुकसान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2300 से अधिक गांव डूब गए हैं, जिससे 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और पांच लाख एकड़ में फसलें तबाह हो गईं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि दुखद बात यह है कि इस दौरान 56 लोगों की जान चली गई और लगभग सात लाख लोग बेघर हो गए, साथ ही बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 3,200 सरकारी स्कूल, 19 कॉलेज, 1,400 क्लीनिक और अस्पताल क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ ही 8,500 किलोमीटर सड़कें और 2,500 पुल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक लगभग 13,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, हालांकि वास्तविक आंकड़ा इससे भी अधिक हो सकता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस समय राज्य संकट में है और दुर्भाग्य से केंद्र सरकार से किसी भी वित्तीय सहायता की उम्मीद नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ में सहायता के लिए दुनिया भर में बसे पंजाबियों तक पहुंच बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मिशन चढ़दी कला की शुरूआत की गई है। उन्होंने बताया कि लगभग 1,000 व्यक्तियों ने पहले ही इस नेक कार्य के लिए अपना समर्थन देने का वादा किया है।

जम्मू में किसानों का दर्द देख भावुक हुए शिवराज!

जम्मू (एजेन्सी)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर किसानों को हुए फसल नुकसान का आकलन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सहायता प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यहाँ पत्रकारों को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि आज मैं जम्मू-कश्मीर की जनता और किसानों का एक विनम्र सेवक बनकर आया हूँ। हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा ने फसलों को भारी नुकसान पहुँचाया है।

भारतीय रेलवे एवं SHRM के सहयोग से मानव संसाधन प्रबंधन पर सेमिनार का आयोजन

CRIS ने HRMS की प्रगति एवं क्रियान्वयन पर प्रस्तुत किया विस्तृत विवरण

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

नई दिल्ली। रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के सहयोग से उत्तर रेलवे मुख्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मानव संसाधन प्रबंधन के समकालीन मुद्दों, श्रेष्ठ प्रथाओं तथा उभरते रुझानों पर विशेष रूप से भारतीय रेल पर केंद्रित विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम में महानिदेशक/मानव संसाधन, अतिरिक्त सदस्य/स्टाफ, अतिरिक्त सदस्य/एच.आर., प्रधान कार्यकारी निदेशक/औद्योगिक संबंध, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/उ.रे., SHRM के गणमान्य सदस्य तथा दिल्ली में पदस्थ सभी आई.आर.पी.एस. अधिकारियों ने भाग लिया।

वहीं दिल्ली से बाहर पदस्थ अधिकारियों ने इस सेमिनार में वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की। इस अवसर पर सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स द्वारा भी एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली की प्रगति और क्रियान्वयन पर विस्तार से जानकारी साझा की गई।

सम्पादकीय

अडाणी को क्लीन चिट

जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट-सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारतीय उद्योग जगत के सबसे बड़े नामों में शुमार अडाणी समूह पर गंभीर आरोप लगाए। आरोपों का स्वरूप इतना सनसनीखेज था कि देखते ही देखते शेयर बाजार में भूचाल आ गया। करोड़ों निवेशकों की मेहनत की कमाई रातों-रात डूब गई और भारत की वैश्विक आर्थिक साख पर प्रश्नचिह्न लगाने की कोशिश हुई। यह केवल एक कॉर्पोरेट विवाद नहीं था, बल्कि भारत की औद्योगिक प्रगति को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश थी। हम आपको याद दिला दें कि हिंडनबर्ग ने अपने तथाकथित रिसर्च रिपोर्ट में अडाणी समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन और फर्जी अकाउंटिंग के आरोप लगाए। रिपोर्ट ऐसे समय में जारी की गई जब अडाणी एंटरप्राइजेस अपना 20,000 करोड़ रुपये का मेगा पब्लिक ऑफर लाने जा रही थी। इसका सीधा असर यह हुआ कि निवेशकों का विश्वास हिल गया और शेयरों में भारी गिरावट दर्ज हुई। चिंता की बात यह थी कि भारत के कुछ विपक्षी दलों ने भी इस रिपोर्ट को सच मानकर इतना दुष्प्रचार किया मानो पूरा अडाणी समूह भ्रष्टाचार और घोटालों का अड्डा हो। संसद से लेकर सड़क तक इस रिपोर्ट को हथियार बनाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हुई। इस राजनीतिकरण ने विदेशी निवेशकों में भी भ्रम फैलाया और भारत के कॉर्पोरेट जगत की विश्वसनीयता पर आघात पहुँचा। लेकिन लगभग दो साल की लंबी और गहन जाँच के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने साफ कह दिया है कि अडाणी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार और आधारहीन थे। जाँच में पाया गया कि जिन वित्तीय लेन-देन को हिंडनबर्ग ने फ़र्जीवाड़ा बताया, वे सब कानूनी रूप से वैध ऋण और पुनर्भुगतान थे। न तो धन का गबन हुआ, न ही किसी अवैध पार्टी को फायदा पहुँचाया गया। यहाँ तक कि जाँच के दौरान लिए गए सभी ऋण ब्याज समेत वापस किए गए। एसईबीआई ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इन लेन-देन को इनसाइडर पार्टी ट्रांजैक्शन्स या धोखाधड़ी नहीं कहा जा सकता। यानी, आरोपों का कोई कानूनी या आर्थिक आधार ही नहीं था। देखा जाये तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते जो हुआ, वह किसी भी देश के उद्योग जगत के लिए चेतावनी है। अडाणी समूह के शेयरों में अचानक भारी गिरावट आई। छोटे-बड़े करोड़ों निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। यह नुकसान केवल अडाणी का नहीं था, बल्कि भारत के वित्तीय बाजार और निवेश माहौल का भी था। गौतम अडाणी ने स्वयं कहा कि इस विवाद से उन्हें सबसे अधिक दुख इस बात का है कि आम निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। यह कथन उनकी व्यक्तिगत पीड़ा को दर्शाता है और यह भी बताता है कि एक सुनियोजित झूठ कितनी बड़ी आर्थिक तबाही ला सकता है। देखा जाये तो हिंडनबर्ग की यह रिपोर्ट मात्र एक रिसर्च डॉक्यूमेंट नहीं थी। यह स्पष्ट था कि इसके पीछे राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ छिपे हुए थे। एक तरफ अमेरिकी और पश्चिमी ताकतें भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और उसके वैश्विक प्रभाव से चिंतित थीं, दूसरी तरफ कुछ घरेलू राजनीतिक दलों ने इसे अपने लाभ के लिए हथियार बना लिया। इस साजिश का परिणाम यह हुआ कि भारत की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने की कोशिश हुई। विदेशी मीडिया ने भी इस विवाद को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया। परंतु समय ने साबित कर दिया कि यह सब केवल भारत की औद्योगिक क्षमता को चोट पहुँचाने का प्रयास था। अब जबकि सेबी की रिपोर्ट ने सभी आरोपों को झूठा सिद्ध कर दिया है, तो सबसे पहला कर्तव्य हिंडनबर्ग और उनके समर्थकों का बनता है कि वे भारत और निवेशकों से माफी मांगें। इसके साथ ही, भारत के विपक्षी दलों को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या केवल राजनीतिक विरोध के लिए वे ऐसी अंतरराष्ट्रीय साजिशों का हिस्सा बन सकते हैं? लोकतंत्र में असहमति और आलोचना जरूरी है, लेकिन जब बात राष्ट्रहित और निवेशकों के विश्वास की हो, तो विपक्ष को भी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। हिंडनबर्ग रिसर्च ने तो अपनी कंपनी बंद कर दी, लेकिन उसकी अप्रमाणित रिपोर्ट के आधार पर देश की संसद का पूरा सत्र ठप करने वाले विपक्षी दल आज भी सक्रिय हैं। उस समय जिस तरह से उन्होंने निराधार आरोपों को हवा दी, विदेशी एजेंडे को ताकत दी और करोड़ों निवेशकों के भरोसे को चोट पहुँचाई, वह केवल राजनीतिक अवसरवाद नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों के साथ खिलवाड़ था। आज जबकि सच सामने आ चुका है और नियामक संस्था ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, विपक्षी दलों को कम से कम देश और जनता से माफी माँगनी चाहिए। बहरहाल, हिंडनबर्ग प्रकरण ने हमें यह सिखाया है कि किसी विदेशी रिपोर्ट या आरोप को आँख मूँदकर सच नहीं मान लेना चाहिए।

जयंती

अनुपम श्याम

जन्म-20 सितम्बर, 1957; मृत्यु-8 अगस्त, 2021) भारतीय फिल्म व टीवी कलाकार थे, जो कि मुख्य तौर से हिंदी सिनेमा और टीवी जगत में सक्रिय रहे। अनुपम श्याम ने वैसे तो कई फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया, लेकिन उन्हें असली सफलता मिली साल 2009 में आए टीवी सीरियल 'मन की आवाज प्रतिज्ञा' से। इस सीरियल में अनुपम श्याम ने ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाया था। यह टीवी सीरियल लोगों को खूब पसंद आया और खासकर अनुपम श्याम का किरदार। इसके बाद वह घर-घर में पहचाने जाने लगे थे।

पुण्यतिथि

नारायण गुरु

जन्म-28 अगस्त, 1855; मृत्यु-20 सितम्बर, 1928) भारत के महान संत एवं समाज सुधारक थे। कन्याकुमारी में मारुतवन पहाड़ों की एक गुफा में उन्होंने तपस्या की थी। गौतम बुद्ध को गया में पीपल के पेड़ के नीचे बोधि की प्राप्ति हुई थी। नारायण गुरु को उस परम की प्राप्ति गुफा में हुई। समाज सुधारक नारायण गुरु द्वारा स्थापित 'शिवगिरि मठ' पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और उनकी समाधि केरल में सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। नारायण गुरु को श्री नारायण गुरु के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म एझावा जाति के परिवार में हुआ था। केरल के जाति-ग्रस्त समाज में उन्हें बहुत अन्याय का सामना करना पड़ा। उन्होंने केरल में सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया, जातिवाद को खारिज कर दिया और आध्यात्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता के नए मूल्यों को बढ़ावा दिया। नारायण गुरु ने मंदिरों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के माध्यम से अपने स्वयं के प्रयासों से दलितों के आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान की आवश्यकता पर जोर दिया।

कल मिलेंगे

डॉक्टर के पास पहुंचा राजू, बोला मैं बीमार हूं
डॉक्टर ने राजू से कहा-आपकी एक किडनी फेल हो गई है...
राजू रोने लगा और कुछ देर बाद आंसू पोंछते हुए बोला.....
ये तो बता दीजिये डॉक्टर साहब कि मेरी किडनी आखिर कितने नंबर से फेल हुई?

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।
RNI No. : DELHIN/2016/70240
Phone No.: 9871221635
E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com
(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

राजनीतिक दलों को कार्यस्थल पर पॉश एक्ट, 2013 से प्राप्त वैधानिक छूट एक नैतिक विडंबना नहीं तो क्या?

कोढ़ में खाज यह कि अब सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि 'राजनीतिक दलों में सदस्यता रोजगार जैसी नहीं है-इसमें न तो नियमित वेतन है और न ही संविदात्मक/नौकरी संबंधी अनुबंध।' सवाल है कि कार्यकर्ता दिन-रात पार्टी की सेवा में लगे रहते हैं या नहीं? इनको मानदेय क्यों नहीं दिया जाता? क्या इसी वजह से ये प्रशासनिक या सामाजिक 'दलाली' करते हैं और किसी तरह निर्वाचित नेताओं के लोकल एजेंट बनकर अपना गुजारा करते हैं

-कमलेश पांडेय

राजनीतिक दलों को महिलाओं की कार्यस्थल सुरक्षा संबंधी कानून प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट (पॉश एक्ट), 2013 से प्राप्त वैधानिक छूट किसी नैतिक विडंबना से कम नहीं है, चाहे इसका विधिक कारण कुछ भी हो! यह हमारी संसद और सर्वोच्च न्यायालय दोनों की नैतिक लापरवाही या खामोशी दोनों का नतीजा है? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह तर्क कि राजनीतिक दल और उनके सदस्यों के बीच पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी का संबंध नहीं होता है, किसी के गले नहीं उतरता है। यह अनुभव की व्यवहारिक कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता है।

यह ठीक है कि उनके बीच पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी का सम्बन्ध नहीं होता, लेकिन दफ्तर और कार्यसंस्कृति दोनों होती है। यहां तक कि टूर के दौरान ठहरने वक्त नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं का कमरा आसपास ही रखा जाता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इससे राजनीतिक दलों व उनके नेताओं को कार्यकर्ताओं के शोषण का अंतहीन अधिकार मिल जाता है! खासकर, जब केंद्र और विभिन्न राज्यों की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस आदि दल किसी कॉरपोरेट शैली से संचालित होती हों, उनके जनसंपर्क यानी प्रचार-प्रसार व कार्यसंचालन का तरीका लगभग वही हो, जब निर्वाचित राजनेताओं के धन भी पांच वर्ष में ही दुगुने-तिगुने से ज्यादा बढ़ जाते हों, जब राजनेताओं व उनके करीबी संगठन के नेताओं पर महिलाओं के शारीरिक शोषण के अनेक आरोप लगते आए हों, वैसे परिदृश्य में सियासी दलों और सियासतदानों को प्राप्त विधिक छूट उनके गलत इरादों को लीगल प्रश्रय नहीं देना है तो क्या है, यक्ष प्रश्न है? भारत के अधिकांश लोगों को पता है कि देश की कानून निर्मात्री संस्था 'संसद', विधानसभा मंडलों में बैठे राजनेतागण खुद को 'अभिजात्य प्राणी' समझते हैं और खुद के फंसने वाला कानून कभी नहीं बनाते। वहीं, अपना सियासी हित साधने के लिए प्रायः द्विअर्थी कानून बनाते हैं। वाकई एक ही प्रवृति के विषयों में अस्पष्ट कानूनों की वजह से ही देश अमेरिका की भांति वकीलों का स्वर्ग बन चुका है। कोई भी नेता दो जगह से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन दो जगहों की मतदाता सूची में नाम निकल जाने पर जानबूझकर बखेड़ा खड़ा किया जाता है। भूमि-भवन-स्वर्ण निवेश सम्बन्धी चीजों, शिक्षा-स्वास्थ्य-कारोबार आदि में अस्पष्ट कानूनों की वजह से निवेशक मालामाल और उपभोक्ता फटेहाल रहते हैं, आदि। सबसे बड़ी विडंबना तो यह कि निर्वाचित होते ही, अपराधी/दुष्कर्मी भी 'माननीय' करार दिए जाते हैं। यह स्थिति प्रशासनिक अधिकारियों व न्यायपालिका के लिए भी शर्मनाक है। साथ ही भारतीय बुद्धिजीवियों, सफल पेशेवर समूहों, विश्वविद्यालयों की पवित्र सोच पर करारा तमाचा है। ऐसे में सुलगता हुआ सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट आरक्षण सम्बन्धी कानून और वक्फ बोर्ड कानून आदि में तो संशोधन करने का अधिकार रखता है, लेकिन नेताओं से जुड़े मामलों में उसकी बुद्धिमत्ता/प्रबुद्ध सोच को 'जंग' लग जाती है, सांप सूंघ जाता है जो वैधानिक 'सामाजिक टेटनस/मानसिक विष' जैसे 'जानलेवा रोगों' की वजह बन जाते हैं।

स्वाभाविक सवाल है कि हमारे राजनेता जेल से चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव प्रचार कर सकते हैं, अपनी सैलरी व भत्ता खुद ही बेहिसाब बढ़ा सकते हैं, राजनीतिक चंदा के लिए 'चोर दरवाजे' छोड़ सकते हैं, संसद के भीतर-बाहर कुछ भी अनाप-शनाप बोल सकते हैं, जिससे सामाजिक-राष्ट्रीय हितों पर चोट पहुंचती है, आदि। इनके कार्यकर्ता पाकिस्तान-बंगलादेश का झंडा लहरा सकते हैं, लेकिन इस पर कभी तर्कसंगत बहस नहीं होती! बेलगाम सोशल मीडिया इनका आधुनिक प्रचार हथियार बन चुका है। क्रिप्टो करेंसी इनके अवैध लेन-देन का साधन बन चुका है।लेकिन एक समान कानून की याद इन्हें कतई नहीं आती। इससे आम व्यवसायियों के कारोबारी हित भी प्रभावित होते हैं।

कोढ़ में खाज यह कि अब सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि "राजनीतिक दलों में सदस्यता रोजगार जैसी नहीं है-इसमें न तो नियमित वेतन है और न ही संविदात्मक/नौकरी संबंधी अनुबंध।" सवाल है कि कार्यकर्ता दिन-रात पार्टी की सेवा में लगे रहते हैं या नहीं? इनको मानदेय क्यों नहीं दिया जाता? क्या इसी वजह से ये प्रशासनिक या सामाजिक 'दलाली' करते हैं और किसी तरह निर्वाचित नेताओं के लोकल एजेंट बनकर अपना गुजारा करते हैं। क्या इसी वजह से भ्रष्टाचार, शिष्टाचार नहीं बन गया है? यह कौन नहीं जानता कि अधिकारियों-जनप्रतिनिधियों/मंत्रियों के बीच दलाली करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं का ही नेटवर्क 'गर्म गोश्त' की भी दलाली करता है, इसलिए इन्हें भी पॉश एक्ट 2013 के दायरे में लाए जाने की जरूरत है। रहस्य न खुले, इसलिए इस धंधे में एक-दूसरे की जान लेना स्वाभाविक बात है! जिसे प्रशासनिक पहुंच के बल पर दबा दिया जाता है। बावजूद इसके कुछ मामले सुर्खियां बन जाते देखे-सुने जाते हैं। बताया जाता है कि पॉश एक्ट की परिभाषा में वही संगठन आते हैं जहाँ "रोजगार और भुगतान" के आधार पर कर्मचारी और नियोक्ता के संबंध मौजूद हैं। चूंकि राजनीतिक पार्टी में कोई महिला कार्यकर्ता बनने का अर्थ 'नौकरी' पाना नहीं है, बल्कि यह केवल "मेम्बरशिप" का मामला है, जिसमें औपचारिक रोजगार संबंध स्पष्ट नहीं होता। ऐसे में राजनीतिक दलों के कार्य के दायरे (जैसे रैलियां, जनसंपर्क, अभियान आदि) को कानूनी तौर पर "स्थायी कार्यालय या कार्यस्थल" की तरह चिन्हित नहीं किया जा सकता- यह अत्यंत गतिशील और अस्थिर होते हैं।

वहीं, चूंकि इस कानून के प्रभाव और विकल्प असरकारक हैं, इसलिए राजनीतिक दलों को मिला छूट इस कानून की सफलता पर संशय पैदा करता है। इस छूट के कारण यदि किसी महिला राजनीतिक कार्यकर्ता को उत्पीड़न का सामना करना पड़े तो वह पॉश एक्ट 2013 के तहत शिकायत नहीं कर सकती है। हालांकि वह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी/IPC) या किसी अन्य आपराधिक कानून का उपयोग कर सकती है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत किया है कि राजनीतिक दलों को पॉश एक्ट, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति स्थापित करने की बाध्यता भी नहीं है। इसलिए स्वाभाविक सवाल है कि राजनीतिक दलों को यह छूट क्यों? क्या वही कानून बनाते-बनवाते हैं, सिर्फ इसलिए! हालांकि, अन्य देशों में कुछ वैकल्पिक उपाय भी उपलब्ध हैं, जिसका भारत में अनुशरण किया जाना चाहिए। जैसे-कुछ देशों में राजनीतिक दल स्वेच्छा से महिलाओं के लिए आंतरिक आरक्षण या शिकायत व्यवस्था अपनाते हैं, किंतु भारत में कानूनी तौर पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। वहीं, राजनीतिक दलों को कार्यस्थल महिला सुरक्षा कानूनों से छूट कोर्ट द्वारा इसलिए दी गई है क्योंकि वहां पारंपरिक वेतनभोगी रोजगार संबंध नहीं पाया जाता और उनकी कार्यप्रणाली "स्थायी दफ्तर" जैसी नहीं होती। इसलिए स्वाभाविक सवाल यह है कि क्या यह एक बिडम्बनात्मक सोच व छूट नहीं है? इस पर देशव्यापी बहस खुद राजनीतिक महिला कार्यकर्ताओं के बीच ही करवायी जानी चाहिए।

बताते चलें कि पॉश एक्ट, 2013 ('कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और प्रतितोष अधिनियम') में 'नियोक्ता' और 'कर्मचारी' की परिभाषा स्पष्ट की गई है, जिसके तहत नियोक्ता की परिभाषा तय है। जैसा कि पॉश एक्ट की धारा 2(जी) में स्पष्ट किया हुआ है, 'नियोक्ता' वह व्यक्ति है जो किसी विभाग, संगठन, प्रतिष्ठान या कंपनी का प्रमुख हो या उसका प्रबंधन, पर्यवेक्षण या नियंत्रण करता हो। यानी संगठन का संचालन करने वाला कोई भी व्यक्ति 'नियोक्ता' माना जाता है। जबकि 'कर्मचारी' की परिभाषा भी व्यापक है-इसमें नियमित, अस्थायी, संविदा, प्रशिक्षु, स्वैच्छिक या एजेंसी के माध्यम से काम करने वाले सभी व्यक्ति आते हैं। वेतन, भत्ते या किसी अन्य प्रकार की पारिश्रमिक या बिना पारिश्रमिक के कार्यरत व्यक्ति भी 'कर्मचारी' की श्रेणी में आते हैं।

इस कानून की मुख्य बातें ये हैं कि 'नियोक्ता' और 'कर्मचारी' की परिभाषा संगठनात्मक संबंध और प्रबंधन के अधिकार से निर्धारित होती है न कि केवल वेतन या रोजगार अनुबंध से। वहीं, पॉश एक्ट, 2013 केवल उन्हीं संस्थाओं पर सीधे लागू होता है, जहाँ यह संबंध स्पष्ट रूप से मौजूद हो। इसप्रकार से पॉश एक्ट में 'नियोक्ता' संगठन के प्रमुख/प्रबंधक और 'कर्मचारी' उस संगठन में किसी भी रूप में (अस्थायी, स्थायी, संविदा आदि) कार्यरत व्यक्ति को कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं के हित संरक्षण से जुड़े इस महत्वपूर्ण कानून पर भी राजनीतिक असर पड़ा है, जिसके दुरुपयोग के बावजूद भारतीय संविधान एक मजबूत, जीवंत और अनुकूल दस्तावेज है, जो आज भी देश की लोकतांत्रिक, न्यायिक और नैतिक नींव का मुख्य आधार बना हुआ है। इसलिए उम्मीद है कि यहां व्याख्या की जा रही नजरिए से भी अविलंब कानूनी संशोधन किए, करवाये जाएंगे।

कहना न होगा कि संविधान सर्वोच्च कानून है, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण करता है और चेक-बैलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। इससे कोई भी व्यक्ति या संस्था विधि से ऊपर नहीं हो सकती, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप के समय भी नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा होती है। जहां तक राजनीतिक दुरुपयोग और संस्थागत सुरक्षा का सवाल है तो संविधान की कुछ धाराओं (जैसे-अनुच्छेद 356) का ऐतिहासिक रूप से दुरुपयोग हुआ है; परंतु सुप्रीम कोर्ट के बोम्मई फैसले जैसे न्यायिक विराम ऐसे दुरुपयोग पर अंकुश लगाने में सफल रहे हैं, जिससे संविधान की संघीय संरचना सुरक्षित बनी रही है।

हाल के वर्षों में भी देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट तथा अन्य संस्थाएं समय-समय पर संविधान के मूल उद्देश्यों की रक्षा के लिए सक्रिय रही हैं, भले ही राजनीतिक दल संविधान को अपने हित के हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। यह हमारे संविधान की अनुकूलनशीलता और लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो सराहनीय है। संविधान में लचीलापन है, जिससे समयानुसार जनता की आवश्यकताओं, सामाजिक संतुलन और नये अधिकारों को संशिधनों के द्वारा सम्मिलित किया जा सकता है। वहीं, संविधान राष्ट्रीय एकता, अल्पसंख्यक सुरक्षा और सामाजिक समावेशन की नींव तैयार करता है, जिससे राजनीतिक उठापटक के बावजूद देश की बुनियादी संरचना अखंड रहती है। इसलिए पॉश एक्ट 2013 के दायरे में राजनीतिक दलों और इस जैसे संगठनों को भी लाये जाने की माकूल कानूनी पहल की जानी चाहिए। इससे महिलाओं के प्रति सुनियोजित आपराधिक सोच में कमी आएगी।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

सेवा पखवाड़ा: जनसेवा से जनविश्वास तक की यात्रा

उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 391 रक्तदान शिविर आयोजित हुए, जिनमें 7287 लोगों ने रक्तदान किया। दिल्ली में 3000 करोड़ रुपये का अधोसंरचना पैकेज घोषित हुआ। मध्य प्रदेश में स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार की पहल शुरू हुई। ये आंकड़े केवल योजनाएँ नहीं बताते, बल्कि यह दशार्ते हैं कि जनता और सरकार के बीच की दूरी कम हो रही है

-पवन शुक्ला

प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन से गांधी जयंती तक चल रहा भाजपा का सेवा पखवाड़ा, जिसने जनता के मन में आशा, विश्वास और आत्मगौरव की नई ऊर्जा जगाई।

भाजपा का सेवा पखवाड़ा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि सेवा को राजनीति की आत्मा बनाने का प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन से शुरू होकर गांधी जयंती तक चलने वाला यह पखवाड़ा राष्ट्र को यह संदेश देता है कि जनसेवा ही जनसंपर्क की सबसे पवित्र भाषा है। जब लाखों कार्यकर्ता झाडू लेकर गली-मोहल्लों में उतरते हैं, रक्तदान करते हैं, पौधारोपण करते हैं और स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, तो यह केवल काम नहीं, बल्कि एक भावना है-मैं भी अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। सेवा पखवाड़े के दौरान हर कोने में सेवा की तस्वीरें दिखीं। कहीं स्कूली बच्चों को मुफ़्त दवाइयाँ मिलीं, कहीं युवाओं ने रक्तदान कर जीवन बचाने का संकल्प लिया। दिल्ली में अधोसंरचना परियोजनाओं की सौगात दी गई तो मध्य प्रदेश में महिलाओं के स्वास्थ्य पर केंद्रित अभियान चला। लखनऊ की सड़कों पर मंत्री से लेकर सफाईकर्मी तक एक साथ झाडू उठाते दिखे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा-हमारे जीवन का मूलमंत्र ही सेवा है। अगर माँ स्वस्थ होगी, तो परिवार सशक्त होगा और परिवार सशक्त होगा तो राष्ट्र सशक्त बनेगा।

उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 391 रक्तदान शिविर आयोजित हुए, जिनमें 7287 लोगों ने रक्तदान किया। दिल्ली में 3000 करोड़ रुपये का अधोसंरचना पैकेज घोषित हुआ। मध्य प्रदेश में स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार की पहल शुरू हुई। ये आंकड़े केवल योजनाएँ नहीं बताते, बल्कि यह दशार्ते हैं कि जनता और सरकार के बीच की दूरी कम हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस अवसर पर कहा-मैं मोदी जी को 24 वर्षों से जानता हूँ। उन्होंने इस पूरे समय में एक भी छुट्टी नहीं ली। जिनका जीवन ही सेवा है, उनके लिए सेवा पखवाड़ा सबसे बड़ा उत्सव है। जनता के बीच भी इस अभियान ने विश्वास जगाया। हरिद्वार के एक बुजुर्ग ने स्वास्थ्य शिविर में भावुक होकर कहा-बेटा, पहले इलाज के लिए हमें शहर भागना पड़ता था। आज दवाइयाँ हमारे दरवाजे पर आ रही हैं। यही असली सेवा है। लखनऊ में एक युवती ने पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान मुस्कुराकर कहा-अब लगता है कि स्वच्छता और हरियाली हमारी भी जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकार की नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा पखवाड़े को केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विकसित भारत के चार स्तंभ-महिला, युवा, गरीब और किसान-को सशक्त करने का अभियान बताया। इस दौरान महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर, युवाओं के लिए रक्तदान और पौधारोपण, किसानों के लिए तकनीकी सहयोग और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ चलाई गईं। हर कोने से जनता की आवाज गूँजी कि अब सेवा सिर्फ. नारा नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी में उतर रही हकीकत है।

यह पखवाड़ा प्रधानमंत्री की जनसेवक छवि को और गहरा करता है। जब एक किसान कहता है अगर यह सेवा निरंतर चले तो गाँव बदल जाएगा और एक छात्र कहता है हम भी देश बदलने की ताकत रखते हैं-तो यह बताता है कि सेवा से ही शक्ति का जन्म होता है। सेवा पखवाड़ा केवल भाजपा या मोदी के लिए राजनीतिक पूंजी नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए आत्मविश्वास और आशा का नया स्त्रोत बन चुका है।

निष्कर्ष: सेवा पखवाड़ा आज एक उत्सव है-सेवा का, सामूहिकता का और आत्मविश्वास का। यह अभियान हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र निर्माण केवल नीतियों से नहीं, बल्कि सेवा की निरंतर धारा से होता है। मोदी जी की छवि आज केवल प्रधानमंत्री की नहीं, बल्कि जनसेवक की है। जनता भी अब यही कह रही है-अगर नेता हमारे साथ खड़े हैं, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। यही वह मनोबल है जो भारत को उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाएगा।

(लेखक लखनऊ उच्च न्यायालय में राज्य विधि अधिकारी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी)
(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

सऊदी से डील होते ही पाकिस्तान पर हो गया पहला बड़ा अटैक, बिछ गई लाशें

(एजेन्सी)।
ऑपरेशन सिंदूर के 132 दिन बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 17 सितंबर को एक डिफेंस डील साइन की है। डिफेंस अग्रीमेंट ये भी कहता है कि अगर एक देश पर हमला हुआ तो दूसरा देश उसे खुद पर भी हमला मानेगा। सऊदी अफसर ने दावा किया कि करार में सभी सैन्य विकल्पों का प्रयोग किया जा सकता है। पाक और सऊदी अरब का कहना है कि ये करार किसी भी तीसरे देश को मद्देनजर रखते हुए नहीं किया गया है। भारत से रिश्ते ताक पर रख कर पाकिस्तान को पालने का सऊदी का फैसला किसी को समझ नहीं आ रहा है।

जानकार इस पूरे खेल के पीछे अमेरिका का हाथ भी बता रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इस डील के साइन होते ही पाकिस्तान पर पहला बड़ा हमला हो गया। वहीं दूसरे हमले की धमकी भी मिल गई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला किया है। सऊदी अरब के साथ हुई डील के बाद पाकिस्तान पर ये पहला बड़ा हमला है। बीएलए ने पाकिस्तान के 13 से भी ज्यादा सैनिकों को मार दिया है। मौत का ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बलूचों ने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। हैरानी की बात देखिए कि एक तरफ तो बलूचों ने पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें बिछा दी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के एक ताकतवर व्यक्ति ने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद को मुसलमानों का नैतिक कर्तव्य बता दिया। यानी अब अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान पर हमलों की बौछार होने जा रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक भाषण में विश्वविद्यालय के तालिबान द्वारा नियुक्त चांसलर मोहम्मद नसीम हक्कानी ने पाकिस्तान सरकार को कठपुतली बताते हुए दावा किया कि उसके कानून यहूदियों और ईसाइयों के प्रभाव में हैं। अमू टीवी स्वतंत्र रूप से इस टिप्पणी के समय या स्थान की पुष्टि नहीं कर सका। तालिबान प्रशासन और उसके उच्च शिक्षा मंत्रालय ने हक्कानी के बयानों पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है।

मोदी भारत-पाक दावे पर ट्रंप को शर्मिंदा होने से बचा सकते थे, लेकिन...बोले राजनीति विज्ञानी ब्रेमर

(एजेन्सी)।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए राजनीति विज्ञानी और यूरेशिया समूह के अध्यक्ष इयान ब्रेमर ने कहा कि वह भारत-पाक युद्ध विराम के अपने दावों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आसानी से शर्मिंदा नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ना कहना पसंद किया। ब्रेमर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम कराने के डोनाल्ड ट्रम्प के बार-बार किये गए दावों का जिक्र कर रहे थे, हालांकि नई दिल्ली ने इस दावे का खंडन किया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार ब्रेमर ने कहा चीनी ट्रंप के सामने डटे रहे हैं। और रूस भी ट्रंप के सामने डटा है और मुझे लगता है कि मोदी उसी स्थिति में हैं।

मोदी भारत-पाकिस्तान मुद्दे पर ट्रंप को शर्मिंदा नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके बजाय, मोदी ने सार्वजनिक रूप से यह कहने का फैसला किया, 'नहीं, आपका इससे कोई लेना-देना नहीं है। वाकई वैश्विक मंच पर ट्रंप को शर्मिंदा कर दिया। इयान ब्रेमर ने उन देशों की ओर इशारा किया जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया है। वह मुख्य रूप से दुनिया को अपनी ताकत दिखाने में रुचि रखते हैं। ब्रेमर ने कहा कि उनका मानना है, 'मैं ताकतवर हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ; आपको मेरी बात सुननी होगी।

इस साल जुलाई में पीएम मोदी ने लोकसभा को संबोधित करते हुए ट्रम्प के भारत-पाक युद्धविराम के दावों को खारिज कर दिया और कहा, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए नहीं कहा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने युद्धविराम पर सहमति होने से एक दिन पहले 9 मई को उन्हें फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन कॉल का जवाब नहीं दिया जा सका क्योंकि पीएम मोदी सेना के साथ बैठक में थे।

'या अली' फेम जुबीन गर्ग का सिंगापुर में निधन

(एजेन्सी)।
लोकप्रिय असमिया गायक जुबीन गर्ग का सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जुबीन असमिया संगीत उद्योग में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। असम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सिंचाई मंत्री अशोक सिंघल ने जुबीन गर्ग के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने (पूर्व में ट्विटर) पर एक भावुक संदेश साझा किया। उनके ट्वीट में लिखा है, "हमारे प्रिय जुबीन गर्ग के असामयिक निधन से गहरा दुख हुआ। असम ने न केवल एक आवाज, बल्कि एक धड़कन भी खो दी है। जुबीन दा एक गायक से कहीं बढ़कर थे, वे असम और राष्ट्र का गौरव थे, जिनके गीतों ने हमारी संस्कृति, हमारी भावनाओं और हमारी भावना को दुनिया के कोने-कोने तक पहुँचाया।"

ट्वीट में आगे लिखा है, "उनके संगीत में, पीढ़ियों को आनंद, सांत्वना और पहचान मिली। उनके निधन से एक ऐसा शून्य पैदा हुआ है जिसे कभी नहीं भरा जा सकता। असम ने अपना सबसे प्रिय सपूत खो दिया है, और भारत ने अपने सबसे बेहतरीन सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक खो दिया है। उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनकी विरासत सदैव प्रेरणा देती रहे। ओम शांति।" पूर्व राज्यसभा सांसद रिपु बोरा ने एक्स पर गायक को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, "हमारे सांस्कृतिक प्रतीक जुबीन गर्ग के असामयिक निधन से गहरा सदमा और दुख हुआ। उनकी आवाज, संगीत और अदम्य भावना ने असम और उससे आगे की पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनके परिवार, प्रशंसकों और प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना।" 1995 के मध्य में, गर्ग बॉलीवुड संगीत उद्योग में काम करने के लिए मुंबई चले गए जहां उन्होंने अपना पहला इंडिपॉप एकल एल्बम चांदनी रात लॉन्च किया। बाद में, उन्होंने चंदा (1996), श्रद्धांजलि वॉल्यूम: 1,2,3 (1996-97), जलवा (1998), युही कभी (1998), जादू (1999), स्पर्श (2000) आदि जैसे कुछ हिंदी एल्बम और रीमिक्स गाने रिकॉर्ड किए। उन्हें गद्दार (1995), दिल से (1998), डोली सजा के रखना (1998), फि़जा (2000), कांटे (2002) जैसी विभिन्न फिल्मों के लिए गाने का मौका मिला। 2003 में, उन्होंने फिल्म मुद्दा-द इश्यू से "सपने सारे" और "ख्वाबों की", फिल्म चुपके से से "मैंगो अगर दिल से तो खुदा", फिल्म मुंबई से अइया मेरा दोस्त से "होली रे" और फिल्म जाल: द ट्रैप से "जो प्यार तुमने" गाया। उन्हें बॉलीवुड में सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म गैंगस्टर से मिला जहां उन्होंने "या अली" गाना गाया। (43) इस गाने ने उन्हें 2006 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक ग्लोबल इंडियन फिल्म अवाड्र्स (जीआईएफए) दिलाया।

शिवकाशी में नए डिजाइन के पटाखों की बंपर मांग

(एजेन्सी)।
रोशनी के त्योहार, दीपावली के नजदीक आते ही, तमिलनाडु के शिवकाशी में, जो आतिशबाजी के केंद्र के रूप में जाना जाता है, पटाखों का उत्पादन जोर पकड़ रहा है। शिवकाशी ज़िले के विरुधुनगर स्थित सोनी विनायगा फायरवर्क्स के मालिक अभिषेक ने इस सीजन की व्यावसायिक बिक्री को लेकर आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इसी साल सभी उत्पाद बिक जाएँगे। इस साल कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। यह पिछले साल जैसी ही है। इस बार कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इस साल सब कुछ अच्छा रहेगा।

इस साल दिवाली सामान्य से पहले आने का ज़िक्र करते हुए, अभिषेक ने कहा कि इस साल दिवाली थोड़ी जल्दी आ गई है। इस साल बिक्री पिछले साल से बेहतर होगी। हमें इस साल ज्यादा बिक्री की उम्मीद है क्योंकि उत्पादन बहुत कम है। इसलिए, मेरा मानना है कि इस साल सभी उत्पादों की माँग ज्यादा रहेगी और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस साल अच्छी कमाई करेंगे। इसके अलावा, सोनी विनायगा फायरवर्क्स के प्रबंध निदेशक हरि राम कुमार ने कहा कि कंपनी ने ग्राहकों के लिए नई किस्में पेश करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि लोग हर साल हमसे नए उत्पादों की उम्मीद करते हैं। इस बार, हमने अलग-अलग रंग और डिजाइन लॉन्च किए हैं। हम देखेंगे कि हमारे ग्राहक नवीनतम किस्मों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। बिक्री हमेशा अच्छी रही है, और इस साल तुलनात्मक रूप से बेहतर है। इस बीच, निमार्ताओं ने इस दिवाली सीजन में बच्चों के लिए विशेष डिजाइन भी पेश किए हैं। जंगल थीम पर आधारित पटाखे भी उपलब्ध हैं, जैसे शेर, भेड़िया और बाघ थीम वाले बक्सों में पैक किए गए पटाखे। इसके साथ ही, सभी उम्र के बच्चों को आकर्षित करने के लिए कार्टून, खेल, संगीत और अन्य थीम पर आधारित पटाखों की कई नई किस्में पेश की जा रही हैं।

अफगानिस्तान पर जीत के बाद श्रीलंकाई क्रिकेटर को मैदान पर मिली पिता के निधन खबर

(एजेन्सी)। श्रीलंका क्रिकेट टीम के युवा खिलाड़ी दुनिथ वेलालागे के परिवार पर बड़ा दुख टूट पड़ा है। उनकी जिंदगी के सबसे कठिन पलों में से एक तब आया जब एशिया कप 2025 में अफगानिस्तान के खिलाफ अहम मैच में जीत हासिल करने के बाद उन्हें ये दुखद खबर दी गई कि उनके पिता सुरंगा वेलालागे का दिल का दौरा पड़न से निधन हो गया है। इस दुखद घड़ी में दुनिथ वेलालागे के लिए क्रिकेट जगत एकजुट दिखा। श्रीलंका के कई दिग्गज क्रिकेटरों और फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि किसी भी बेटे को ये दर्द सहना नहीं चाहिए कि वह मैदान पर खेल रहा हो और अचानक पिता को खोने की खबर मिले। सूत्रों के मुताबिक, श्रीलंका टीम मैनेजर और पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सनत जयसूर्या ने मैच के बाद दुनिथ वेलालागे को ये दुखद समाचार दिया। जिसके बाद दुनिथ पूरी तरह टूट गए। टीम के साथी खिलाड़ियों ने इस कठिन समय में उन्हें संभालने की कोशिश की और भावनात्मक सहारा दिया। सिर्फ 21 साल के दुनिथ वेलालागे को श्रीलंका क्रिकेट का उभरता सितारा माना जाता है। इतनी कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बना चुके इस खिलाड़ी के पिता हमेशा उनके सबसे बड़े समर्थक रहे।

पुलिस ने रतनपुर गांव से जाली नोट के साथ दो तस्करों को किया गिरफ्तार

एसबी ब्यूरो प्रमुख/मृगांक शेखर सिंह

जमुई। जमुई जिला अंतर्गत गिद्धौर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पांच सौ रुपए के सात जाली नोट बरामद करने के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। उक्त जाली नोट को तस्कर रतनपुर के एक स्थानीय दुकान में समान खरीददारी के क्रम चलाने का प्रयास कर रहे थे। जिसपर गिद्धौर पुलिस को मामले की सूचना स्थानीय दुकानदार द्वारा दी गयी। गिद्धौर पुलिस को सूचना मिलते ही मामले में थानाध्यक्ष दीनानाथ सिंह द्वारा इसकी सूचना जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारियों को दी।

वहीं थानाध्यक्ष के नेतृत्व में जाली नोट कारोबारी के धर पकड़ को ले इस मामले में टीम गठित कर रतनपुर गांव से दोनों जाली नोट तस्कर को पांच सौ के जाली नोट के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले में एसडीपीओ सतीश सुमन के दिशा निर्देश पर गिद्धौर पुलिस द्वारा थाना कांड संख्या 215/25 दिनांक 18/09/25 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कानूनी कारवाई की जा रही है।

इस अभियान में थानाध्यक्ष दीनानाथ सिंह अवर निरीक्षक प्रभात राय मनीष कुमार, डायल एक सौ बारह के पीटीसी शैलेन्द्र कुमार सिपाही 279 शिव जी कुमार के अलावे सशस्त्र बल के जवान अभियान में मौजूद रहे।

तेजस्वी यादव की अधिकार यात्रा को वैशाली जिला में ऐतिहासिक बनाने के लिए राजद कोर कमिटी की हुई समीक्षा बैठक

एसबी ब्यूरो प्रमुख/डॉ. संजय

हाजीपुर। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, तेजस्वी प्रसाद यादव के 20 सितंबर शनिवार को वैशाली जिला में बिहार अधिकार यात्रा को ऐतिहासिक बनाने को लेकर गुरुवार को राजद कोर कमिटी की समीक्षा बैठक स्थानीय दिघी स्थित एक होटल के सभागार में वैधनाथ चंद्रवंशी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिसमें प्रदेश स्तरीय नेता, प्रवक्ता, विधायक, एम एल सी तथा जिला स्तरीय राजद के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया और तेजस्वी यादव के आगमन पर होनेवाली तैयारी और व्यवस्था पर विशेष समीक्षा की। इस संदर्भ में एम एल सी, सुनील सिंह ने मीडिया को बताया कि उनके आगमन पर वैशाली जिला में विशेष व्यवस्था की जा रही है। पातेपुर से हाजीपुर तक लगभग चार सौ तोरण द्वार, बीस हजार मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर के साथ हजारों किसान और लाखों की संख्या में राजद कार्यकर्ता तथा आम नागरिक, उनके भव्य स्वागत में होंगे। वे बिहार के भविष्य हैं। इसलिए उनकी यह यात्रा ऐतिहासिक होगी। उन्होंने बताया कि बिहार की आम जनता यह समझ चुकी है कि उनके जैसा कोई नहीं चाहे किसी भी क्षेत्र की बात कर लें। उनकी यात्रा की शुरूआत पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्वाह्न ग्यारह बजे दिन में बरडीहा से शुरू होगी जहां पर वे जनसभा को संबोधित करेंगे। अपराह्न एक बजे दिन में महुआ पहुंचने पर गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद चार बजे संध्या में सेन्दुआरी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने मीडिया के साथ प्रेसवार्ता में बताया कि जहानाबाद, नालंदा, बेगुसराय, बख्तियारपुर, मोकामा, पटना में उनकी यात्रा के क्रम में लाखों की संख्या में लोग जुड़े।

इसी क्रम में वैशाली जिले में भी उनका आगमन होने पर विशेष तैयारी और व्यवस्था के लिए कोर कमिटी की बैठक आयोजित हुई है जिसमें प्रदेश स्तरीय राजद नेता, प्रवक्ता, विधायक, एम एल सी सहित जिला स्तरीय नेता उपस्थित होकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस कोर कमिटी की बैठक में महुआ विधायक, डॉ मुकेश रौशन, विधायक, छोटे लाल राय, राजद प्रवक्ता, चित्तरंजन गगन, बीके सिंह, एम एल सी, मो. फैसल, नगेन्द्र कुमार रिंकू, अशोक पाण्डेय, पूर्व विधायक, प्रेमा चौधरी और राजद नेत्री, नेता, देव कुमार चौरसिया, अशोक पासवान सहित कई नेता मौजूद रहे।

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को 4 दिन में सडकों के गडडे भरने के दिए निर्देश

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजेश कुमार

पंचकूला। जिला उपायुक्त पंचकूला सतपाल शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को 4 दिन में शहर की सडकों के गडडे भरने का कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। उपायुक्त ने लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित बैठक में ये निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि उन्होंने स्वयं दौरा कर सडकों की स्थिति का जायजा लिया है हालात सड़कों की अच्छी नहीं है। सतपाल शर्मा ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि अधिकारी अपने संबंधित क्षेत्रों में सडकों के गडडे अगले 4 दिनों में दुरूस्त करें, वे स्वयं सड़कों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने पीडब्ल्यूडी बीएंड आर कार्यकारी अभियंता अरुण, सिंहमार और आशीष को पिंजौर कालका की सड़कों के गड्ढे भरने का कार्य अपने एरिया की सड़कों के गड्ढे भरने के कार्य को 4 दिनों में पूरा कर रिपोर्ट करने के कहा इसके उपरांत वे स्वयं सड़कों का निरीक्षण करेंगे। उन्होने निर्देश दिए कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। इस संबंध में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। इस अवसर पर एसडीएम कालका संयम गर्ग, नगर निगम के एसडीओ अजय गौतम, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता एनके पायल, एचएसएएमबी के कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी बीएंड आर कार्यकारी अभियंता आशीष कुमार, पीडब्लयूडी बीएंड आर कार्यकारी अभियंता अरुण सिंहमार, पीएमडीए कार्यकारी अभियंता अरविंद कुमार, नगर परिषद कालका सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

महिला सुरक्षा पर डीसीपी का सख्त संदेश, अपराधी को होना चाहिए शर्मिंदा, न कि पीड़िता को

पढ़ी-लिखी हो, बोलना सीखो, अत्याचार सहना बंद करो, पुलिस आपके साथ है-भरोसा करो

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजेश कुमार

पंचकूला। सेवा पखवाड़ा के तहत पुलिस आयुक्त शिवास कविराज के निर्देशानुसार आज डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने पीजी कॉलेज सेक्टर-1 में महिला सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर डीसीपी ने कॉलेज छात्राओं, स्कूलों के विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस वॉलंटियर्स तथा कॉलेज स्टाफ के साथ महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर करीब 2 घंटे विस्तार से चर्चा की।

डीसीपी ने छात्राओं को सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने, अंजान लोगों को फॉलो न करने और लापरवाही से बचने की सलाह दी। उन्होंने फोटो व वीडियो के दुरुपयोग तथा डीपफेक जैसे खतरों के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं और शिक्षकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उन्होंने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। डीसीपी ने कहा कि पुलिस से डर केवल तभी लगना चाहिए जब कोई गलत कार्य किया हो, अन्यथा आत्मविश्वास के साथ पुलिस से मिलें और अपनी बात रखें। यदि बाजार, बस स्टैंड या शिक्षण संस्थान के बाहर छेड़छाड़ या पीछा जैसी घटना होती है तो तुरंत 112 पर कॉल करें, जहां शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि समस्या का समाधान न मिले तो सीधे एसीपी या डीसीपी को फोन या संदेश के माध्यम से सूचित किया जा सकता है। छात्राएँ अपनी शिकायत अपने शिक्षक या माता-पिता के सहयोग से भी दर्ज करा सकती हैं। डीसीपी ने स्पष्ट कहा कि यदि कोई आपके साथ बदतमीजी, छेड़छाड़ या उत्पीड़न करता है, चाहे घर में हो या बाहर, तो वही गुनहगार है और शर्मिंदा भी उसे ही होना चाहिए। छात्राओं को यह भय नहीं रखना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे या उन्हें जज करेंगे। उन्होंने कहा मैं आपके साथ हूँ, पुलिस विभाग आपके साथ है डरना नहीं है। आप पढ़ी-लिखी हैं, बोलना सीखें, आत्मनिर्भर बनें, मजबूत बनें, पर्दा डालना और चुप रहना बंद करें, पुलिस पर विश्वास रखें। उन्होंने छात्राओं को ट्रिप मॉनिटरिंग की मदद से सुरक्षित यात्रा करने की सलाह भी दी। डीसीपी ने कहा कि यह भ्रांति न रखें कि हर शिकायत पर मुकदमा दर्ज होगा, पुलिस बार-बार बुलाएगी और उलझन बढ़ेगी, क्योंकि कई मामलों में पुलिस सामान्य कार्रवाई से भी समाधान कर देती है। उन्होंने छात्राओं से बेझिझक सामने आने की अपील की।

इस अवसर पर महिला सेल इंचार्ज इंस्पेक्टर राजेश कुमारी ने भी छात्राओं को महिला सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दीं।

बछवाड़ा में लक्ष्मी ज्वेलर्स का दरवाजा तोड़कर तीन लाख की लूट

एसबी ब्यूरो

बछवाड़ा (बेगूसराय)। जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत रानी तीन पंचायत के रानी चौक स्थित एक ज्वेलर्स दुकान में देर रात चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और नगद रुपए लूट लिया है। वारदात के दौरान ग्रामीण चौकीदार को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट भी की गई। चोरों ने दुकान का शटर काटकर दुकान के अंदर प्रवेश किया और तिजोरी से लगभग डेढ़ किलो चांदी के पायल, लगभग 10 ग्राम सोने के जेवरात और 15,000 रुपए नगद ले लिया।

दुकानदार शंभू साह ने बताया कि वह पिछले ढाई वर्षों से रानी चौक स्थित डॉ. चंद्रभूषण ठाकुर मार्केट में दुकान चला रहे हैं। बुधवार शाम को दुकान बंद कर घर जाने के बाद देर रात मकान मालिक राजा ठाकुर ने उन्हें चोरी की सूचना दी। दुकान पहुंचने पर उन्होंने देखा कि घटना घटित हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार, ग्रामीण चौकीदार उमाशंकर पासवान के साथ मारपीट कर उन्हें बंधक बनाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मनीष, डीएसपी कृष्ण कुमार, तेघड़ा इंस्पेक्टर संतोष कुमार और थानाध्यक्ष परेंद्र कुमार सहित अन्य पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने घटना स्थल का मुआयना करते हुए कई निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक मनीष ने पुष्टि की है कि रानी तीन पंचायत के रानी चौक स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स में देर रात चोरों ने शटर काटकर चौकीदार के साथ मारपीट कर बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक टीम, स्क्वाड डॉग टीम, टेक्निकल टीम और सीसीटीवी फुटेज की मदद से जल्द ही घटना का उद्वेदन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय, देहरादून में राज्य स्तरीय दिशा समिति की पहली बैठक आयोजित की गई

संजना भारती संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय, देहरादून में राज्य स्तरीय दिशा समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। बैठक में कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं खेल से जुड़ी योजनाओं की कार्यवाही पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग शीघ्र इसका लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और विभागों के बीच आपसी समन्वय अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बल दिया कि राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए लगातार ठोस और सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी युग में योजनाओं की निगरानी और सफल संचालन हेतु आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि सूचनाओं की त्वरित उपलब्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने से योजना क्रियान्वयन की गति में उल्लेखनीय सुधार होगा। किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुँचाने के लिए सभी विभागों द्वारा समन्वित प्रयास करना आवश्यक है। कृषि और ऊर्जा क्षेत्र पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित पंपों की स्थापना की गति तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को न केवल सिंचाई के साधन सुलभ होंगे बल्कि सौर ऊर्जा के उपयोग से दीर्घकालिक रूप से ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी प्राप्त होगी। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शेष गांवों को शीघ्र सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क संपर्क किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला है, और राज्य के दुर्गम इलाकों में निवास कर रहे लोगों की सुविधाओं तथा आर्थिक अवसरों के विस्तार के लिए यह आवश्यक है। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों की प्रगति की भी गहनता से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता योजनाओं को और प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ताकि राज्य के हर नागरिक के जीवन स्तर में सार्थक सुधार हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं की सफलता के लिए शासन के साथसाथ जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय जनता की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे नियमित रूप से जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर योजनाओं की प्रगति साझा करें और लोगों को इनसे अधिकाधिक लाभान्वित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता जनता की सुविधा और सुखसुविधा है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी विभागों को पूरी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता से कार्य करना होगा। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, डॉ. कल्पना सैनी, विधायकगण श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, श्रीमती रेनू बिष्ट, श्री सुरेश गढ़िया, श्री शक्तिलाल शाह, श्री हरीश धामी एवं श्री मनोज तिवारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री धामी ने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत नगर निगम देहरादून द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया

संजना भारती संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत शुक्रवार को नगर निगम देहरादून द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के तहत प्रदेश में स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक जागरूकता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जन सुविधाओं के लिए बहुद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोगो को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने सभी को सेवा पखवाड़ा की गतिविधियों में सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र भट्ट, श्री नरेश बंसल, मेयर श्री सौरभ थपलियाल, अन्य जन प्रतिनिधिगण मौजूद थे।

दिव्यांगजनों को निशुल्क मिलेंगे कृत्रिम अंग, केकेएम कॉलेज के परिसर में लगेंगे शिविर

एसबी ब्यूरो प्रमुख/मृगांक शेखर सिंह

जमुई। दिव्यांगजनों के लिए एडिप योजना के तहत कृत्रिम अंग (कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पैर एवं कैलीपर) निःशुल्क प्रदान किये जाने के लिए ऑन द स्पॉट निःशुल्क वितरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जमुई के डीएम नवीन ने दिव्यांगजनों की सुविधा की दृष्टिगत जिले के कि कॉलेज परिसर में दिनांक 27 सितंबर 2025 को लगने वाले शिविरो का रोस्टर जारी किया है। जिलाधिकारी ने विकेश कुमार जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी सह प्रभारी सहायक निदेशक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को शिविर का नोडल अधिकारी तथा सुश्री मुनमुन पांडे जिला प्रबंधक, बुनियादी केंद्र खैरा को नामित किया है, जो शिविरों के सफल शिविर संचालन सुनिश्चित करेगें। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय वायो श्री योजना द्वारा एडिप योजना के तहत दिव्यांगजन को ऑन द स्पॉट निःशुल्क चिन्हाकन/वितरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह संस्था भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) कानपुर के सहयोग से दिव्यांगजन को उच्चकोटि के कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पैर एवं कैलीपर इत्यादि उपकरण निःशुल्क प्रदान करेगी। इस शिविर मे चिन्हाकन के साथ ही उसी दिन कृत्रिम अंग/कैलीपर प्रदान किये जायेगे।

जारी रोस्टर के अनुसार 27 सितंबर को शिविर स्थल पर आवश्यक तैयारी हेतु नोडल पदाधिकारी सहायक नोडल पदाधिकारी एवं एलेन को कानपुर के प्रतिनिधियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने एवं कॉलेज के परिसर में उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु प्राचार्य केकएम कॉलेज जमुई को निर्देशित किया। वहीं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने संबंधित प्रखंड अंतर्गत चिन्हाकिंत वृद्धजनों की सूची दिव्यांग जन सशक्तिकरण कोषांग जमुई से प्राप्त कर सभी वृद्धजनों को निर्धारित तिथि को शिविर स्थल पर उपस्थित होने से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने को कहा। शिविर स्थल की साफ सफाई की व्यवस्था कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद जमुई को निदेशित किया। साथ ही नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी जमुई तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी जमुई के द्वारा 10 विकास मित्रों को प्रतिनिधि शिविर कार्य में सहयोग हेतु निदेशित किया। उन्होंने शिविर स्थल पर आवश्यक सुविधाओं सहित एंबुलेंस एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति हेतु असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया। जिलाधिकारी ने जिला अग्निशमन पदाधिकारी को शिविर स्थल पर अग्निशमन वाहन की प्रतिनियुक्ति करने का दिया। उन्होंने शिविर स्थल पर दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति हेतु विशेष कार्य बात अधिकारी जिला गोपनीय शाखा जमुई को संयुक्त रूप से आदेश निर्गत किया।

नोटिस

मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, मुजफ्फरनगर

विविद वाद सं. 2/2025

माया पत्नी स्व. राकेश व अन्य (याचीगण) निवासीगण ग्राम बिहारी थाना सिखेड़ा जिला मुजफ्फरनगर

बनाम

विजेन्यत चंदेला पुत्र ज्ञानेंद्र सिंह निवासी 118, भीमनगर, विजयनगर, गाजियाबाद, (स्वामी वाहन सं. UP14 CT 9718)

सूचित किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु वाद दायर किया गया है। विपक्षी विजेन्यत चंदेला पुत्र ज्ञानेंद्र सिंह निवासी 118, भीमनगर, विजयनगर, गाजियाबाद (स्वामी वाहन सं. UP14 CT 9718) को आदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 09.10.2025 को प्रातः 10:30 बजे न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता सहित उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति की दशा में वाद का निस्तारण एकतरफा किया जाएगा।

आज्ञा से

मुन्सरिम/ सहायक लेखाकार

मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, मुजफ्फरनगर

उत्तर मध्य रेलवे

No.: JHS-DY-CEE-C-T-06-2025/NIT **दिनांकः** 16.09.2025

ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना

उप. मुख्य विद्युत अभियन्ता (निर्माण), उत्तर मध्य रेल, झाँसी, भारत के राष्ट्रपति के लिये और उनकी ओर से निम्न लिखित कार्य हेतु **एक पैकेट** सिस्टम पर ऑन लाइन (E-Tendering) के माध्यम से खुली निविदा आमन्त्रित करते हैं। निविदा **दिनाँक 07.10.2025** को **15.00 बजे** तक website **http://www.ireps.gov.in** पर ऑन लाइन जमा की जा सकती है। निविदा के विवरण निम्नानुसार है:-

निविदा संख्याः E-Tender Notice No.- JHS-DY-CEE-C-T-06-2025

कार्य का नामः झांसी मंडल के उत्तर मध्य रेलवे में खैरार कॉर्ड लाइन (16.4 किमी), महोबा कॉर्ड लाइन (3.7 किमी) और हरपालपुर-बेलाताल (25 किमी) के दोहरीकरण के लिए बनाई जा रही नई लाइन के शेष कार्य (कुल = 16.4 + 3.70 + 25 = 45.10 किमी) और जरूरत के अनुसार अन्य आवश्यक स्थानों के विद्युतीकरण के संबंध में 25 केवी, एसी, 50 हट्र्ज, ओएचई (ओवर हेड इक्विपमेंट) का डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग।

अनुमानित लागतः ₹ 173527619.39	**धरोहर राशिः** ₹ 1017600.00
निविदा खोलने का दिनांक: 07.10.2025	**वैद्यता अवधिः** 90 दिन
कार्य पूर्ण होने की अवधिः 12 माह हार्वेस्ट एवं मानसून अवधि सहित	

नोटः पूर्ण विवरण और निविदा जमा करने के लिए कृपया भारतीय रेलवे की वेबसाइट **http://www.ireps.gov.in** देखें। **1696/25 (A)**

f North central railways | @CPRONCR | www.ncr.indianrailways.gov.in

भारतीय रेल

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

सं. 2025/TK-II/22/6/3 (ZITMS) नई दिल्ली, दिनांक: 19.09.2025

शुद्धिपत्र संख्या 4

विषय : ई–निविदा क्रमांक टीएम–2501 शून्य एकीकृत रेलपथ निगरानी प्रणाली (ZITMS) की खरीद और इसके संचालन और रखरखाव के लिए

निविदा की अंतिम तिथि, दिनांक 25.09.2025 (बृहस्पतिवार 15:00 बजे) से बढ़ाकर 30.10.2025 (बृहस्पतिवार 15:00 बजे) कर दी गई है।

निविदा के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेगी।

(अनुराग कुमार)
कार्यकारी निदेशक/रेलपथ आधुनिकीकरण
रेलवे बोर्ड
दूरभाष 011–47845530
ई मेल: anuragkumar.dtk2@gmail.com

2892/2025

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उत्तर मध्य रेलवे

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर मध्य रेलवे

बाल्मीकी चौराहा, नवाब यूसुफ रोड, प्रयागराज - 211001

वर्ष 2025-26 में स्काउट्स एवं गाइड्स कोटा के अंतर्गत खुली भर्ती

रोजगार सूचना सं. S&GQ 2025-26 दिनांक : 18/09/2025

नोटिफिकेशन जारी करने की तिथि : 18.09.2025

ऑनलाईन आवेदन की प्रारंभिक तिथि : 19.09.2025

ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि व समय : 18.10.2025, 23:59 बजे तक

उत्तर मध्य रेलवे में स्काउट्स एवं गाइड्स कोटा वर्ष 2025-26 में खुली भर्ती के तहत ग्रेड पे रू. 1900/- एवं 1800/- (7 वें सीपीसी के बाद संशोधित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-02 एवं 01) में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक और स्काउट्स एवं गाईड्स योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से नीचे दर्शाये गये कोटे के विरूद्ध ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि **18.10.2025 रात्रि 23:59 बजे** तक आमंत्रित किए जाते है।

क्र.सं.	पद	मैट्रिक्स लेवल (7th सीपीसी)	पदों की संख्या	पदों का आवंटन
1	लेवल-2	पे मैट्रिक्स लेवल-2 (ग्रेड पे रू. 1900/-)	02 (दो)	उत्तर मध्य रेलवे पर
2	लेवल-1	पे मैट्रिक्स लेवल-1 (ग्रेड पे रू. 1800/-)	06 (छः)	02 पर प्रत्येक झांसी, प्रयागराज एवं आगरा मंडलों हेतु।

➤ उपरोक्त कोटा सभी श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु हैं, बशर्ते वे न्यूनतम योग्यता/अर्हता रखते हों।

➤ रोजगार सूचना, आवेदन पत्रों का प्रारूप एवं अन्य सभी विवरण, यथा शैक्षणिक योग्यता, आयु, भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क, आवेदन कैसे करें तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज के वेबसाइट **www.rrcpryj.org** पर दिनांक **18.09.2025** से उपलब्ध है।

अध्यक्ष,
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

1694/25(AS)

North central railways | www.ncr.indianrailways.gov.in | @ CPRONCR

हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने करनाल में पीएचसी का किया दौरा

■ डॉक्टरों व पैरा मेडिकल स्टॉफ से किया आह्वान स्वास्थ्य सेवाओं को बनाएं और बेहतर

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने शुक्रवार को करनाल जिला के खरकाली गांव (मधुबन) के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) का दौरा किया। उन्होंने पीएचसी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली और इन्हें बेहतर बताया। उन्होंने सभी डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ से आह्वान किया कि वे स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए कार्य करें।

राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष शुक्रवार शाम गांव खरकाली की पीएचसी पहुंचे। उन्होंने डिस्पेंसरी के ओपीडी रजिस्टर और वहां उपलब्ध दवाओं की जानकारी ली। पीएचसी में इलाज के लिए आए टीबी मरीजों से बात की और दो मरीजों को पोषण किट भी वितरित की। होम्योपैथी डॉक्टर से प्रारंभिक स्तर पर रोगी का इलाज करने के तरीके और टीबी रोगियों को अच्छे ढंग से इलाज करने को कहा। उन्होंने वैक्सीन कक्ष में रखी दवाओं व डीप-फ्रिजर के तापमान को भी जांचा। पीएचसी के सब-सेंटर में मौजूद पैरा मेडिकल स्टाफ से टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं व बच्चों की देखभाल, परिवार नियोजन आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन कक्ष, प्रसवोत्तर वार्ड, आयुष कक्ष, दंत चिकित्सक कक्ष, पट्टी व टीकाकरण कक्ष, पुरूष वार्ड का भी दौरा किया।

इस मौके पर उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं को बेहतर बताया। साथ ही इन सेवाओं को और बेहतर करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि यहां का स्टॉफ पूरी निष्ठा से नियमित रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरी पेशे का धर्म सेवा है। लोग डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं। मरीज ठीक होकर उन्हें जो दुआएं देंगे वही उनकी असली जमा पूंजी है।

इस मौके पर करनाल के डीसी उत्तम सिंह, एसपी गंगा राम पूनिया, सीएमओ डॉ पूनम चौधरी, एसडीएम घरौंडा राजेश सोनी, एसएमओ संदीप अबरोल, एएमओ डॉ. सतपाल, डीएसपी मनोज कुमार, एमओ डॉ. माला, बीडीपीओ मोनिका आदि मौजूद रहे।

सुरेन्द्र घुम्मन तीसरी बार सर्वसम्मति से बने भाकियू के जिला अध्यक्ष

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। स्थानीय दीनबंधु सर छोटू राम किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के तत्वाधान में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ किसान नेता प्रेमचंद शाहपुर ने की। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतनमान विशेष तौर पर मौजूद रहे। करीब तीन घंटे चली बैठक में भाकियू की जिला स्तरीय कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। जिसमें सरदार सुरेन्द्र सिंह घुम्मन को तीसरी बार जिला प्रधान की जिम्मेदारी मिली है। बैठक में जिलाभर से सैंकड़ो किसान शामिल रहे।

सर्वसम्मती से गठित की गयी कार्यकारिणी की भाकियू के पूर्व प्रदेश संगठन सचिव श्याम सिंह मान ने घोषणा की। जिसमें सर्वसम्मती से चौधरी नेकी राम मंढान को जिला करनाल का प्रभारी, चौधरी बाबुराम डाबरथला को जिला संरक्षक, सरदार सुरेंद्र सिंह घुम्मन को जिला प्रधान, सतीश कुमार कांबोज को उप प्रधान, सरदार सेवा सिंह गौराया को उप प्रधान, संजीव कुमार सैनी को उप प्रधान तथा सुरेंद्र बेनीवाल को महासचिव, राजकुमार नौतना को कोषाध्यक्ष, रमेश पंवार को संगठन सचिव नियुक्त किया गया। इसी प्रकार मुकेश राणा व रितिक मढाढ को मीडिया सचिव व सरदार परगट सिंह को प्रचार मंत्री, राम दुरेजा को सचिव, सुरेंद्र सांगवान को प्रवक्ता और बलबीर सिंह तेवतिया को कानूनी सलाहकार नामित किया गया।

इस अवसर पर जोगिन्द्र झींडा, रणजीत सिंह, सतबीर सिंह, जोगिन्द्र बस्तली, राजिन्द्र राणा, धनेतर राणा, रामफल नरवाल नरुखेडी, रणबीर कतलाहेडी, दिलावर सिंह डबकोली, डॉ सत्यवीर तौमर, रामेश्वर दादुपुर, कुलदीप राणा, देवेन्द्र सांगवान, विनोद राणा सहित काफी संख्या में किसान मौजूद थे।

पौधारोपण है जीवन का आधार: विधायक सतपाल जांबा

■ विधायक सतपाल जांबा ने गांव टयोंठा के राजकीय स्कूल परिसर में किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

पूंडरी। विधायक सतपाल जांबा ने कहा की वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अधिक से अधिक पौधे लगाएं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना योगदान दें।

विधायक सतपाल जांबा शुक्रवार को सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत हरियाणा वन विभाग द्वारा गांव टयोंठा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपना संबोधन दे रहे थे। विधायक ने स्कूल परिसर में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए और लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। विधायक ने कहा कि देश में प्रदेश में सेवा पखवाड़ा चला हुआ है। आइए हम सब मिलकर प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लें और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ व हरा-भरा वातावरण दें। उन्होंने कहा कि पेड़ हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि वे हमें ऑक्सीजन, फल, फूल, छाया, लकड़ी और औषधियां प्रदान करते हैं। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में वृक्षों का योगदान सबसे अधिक होता है। पौधे धरती को हरा-भरा और सुंदर बनाते हैं। ये वर्षा लाने में सहायक होते हैं, मिट्टी को कटाव से बचाते हैं और वायु को स्वच्छ करते हैं। प्रदूषण की समस्या को कम करने में भी वृक्ष अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें, तो हमें अभी से पेड़-पौधे लगाने होंगे और उनकी सुरक्षा करने का संकल्प लेना होगा। हर व्यक्ति यदि प्रतिवर्ष एक पौधा लगाए और उसे बड़ा करे, तो धरती पर हरियाली और जीवन दोनों सुरक्षित रहेंगे।

विधायक सतपाल जांबा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में देश व प्रदेश तरक्की के रास्ते पर है। हमें अपने देश को विकसित देश बनाना है, इसके लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। स्वच्छता की तरफ विशेष ध्यान देना है और लोगों को जागरूक भी करना है। सभी युवा श्रमदान जरूर करें।

कैथल रोजगार मेले में 194 युवाओं को प्रदान किए जॉब ऑफर लेटर

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। शुक्रवार को जिला रोजगार कार्यालय कैथल के सौजन्य से जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कैथल में रोजगार मेले व सेवा पखवाड़े का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रोजगार विभाग, राजकीय आईटीआई कैथल, एमएसएमई विभाग कैथल के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मेले में 194 प्रार्थियों को जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए गए।

मेले में आईटीआई अध्यक्ष नरेंद्र मिगलानी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और सेवा पखवाड़ा के लिए विशेष अतिथि के रूप में यशपाल प्रजापति शामिल हुए।

जिला रोजगार अधिकारी ममता कुमारी ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत रोजगार सहायता शिविर एवं प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। इसमें स्वरोजगार करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा प्रार्थियों को उचित मार्गदर्शन व ऋण संबंधी जानकारी दी गई। इसके अलावा रोजगार विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे सक्षम युवा योजना व सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना बारे पंजीकरण व मार्गदर्शन दिया गया। इसके अतिरिक्त युवाओं को करियर काउंसलिंग की गई व इच्छुक प्रार्थियों को सरकारी क्षेत्र व प्राइवेट जॉब से संबंधित जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि हर महीने रोजगार विभाग द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है।

इस माह के मेले के दौरान एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 30 युवाओं को जॉब ऑफर लेटर दिया। वहीं एलआईसी जीवन बीमा कैथल ने 20, भारत फाइनेंस इन्क्लूशन कैथल ने 15, स्वराज महिंद्रा मोहाली ने 18, गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैखिंग कंपनी मोहाली ने 58, रुलदू राम एंड संस कैथल ने 28, महालक्ष्मी पॉलीमर कैथल ने 10, पुखराज हेल्थ केयर करनाल ने 15 युवाओं को जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए।

स्वच्छता को केवल आदत ही नई अपितु जीवनशैली बनाएं-विधायक योगेन्द्र राणा

संजना भारती संवाददाता

असंध। विधायक योगेन्द्र राणा की अध्यक्षता में शुक्रवार को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, असंध के कार्यालय में खंड असंध और मुनक की सभी पंचायतों के सरपंचों की बैठक हुई। इस बैठक का उद्देश्य गांवों को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में सरपंचों के साथ मिलकर काम करना था।

विधायक ने सरपंचों से गाँवों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने और लोगों में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, स्वच्छता सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन-शैली है। जिस तरह हम हर सुबह ब्रश करते हैं, उसी तरह स्वच्छता भी हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बननी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सरपंचों को गाँवों की स्वच्छता को अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए काम करना चाहिए और इस अभियान को एक संकल्प के रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ाना चाहिए, विधायक ने कहा कि जैसे हमारे स्थानीय सांसद और केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में स्थित कूड़े के ढेर को समतल करने का संकल्प लिया है, उसी तरह स्वच्छता अभियान को संकल्प मानकर सभी सरपंचों को भी इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानकर कार्य करना चाहिए , विधायक योगेन्द्र राणा की योजना इस बार हल्के के विकास खंड असंध, मुनक और चिढ़ाव में सफाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित करने की है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस बार हरियाणा में इस पखवाड़े के संयोजक की जिम्मेदारी विधायक योगेन्द्र राणा को सौंपी गई है। इसी क्रम में वे व्यक्तिगत रूप से सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं।

17 सितंबर को उन्होंने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर असंध की फल मंडी से स्वयं इस स्वच्छता अभियान की शुरूआत की थी। इस बैठक में एसडीएम राहुल (आईएएस), खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रशांत कुमार, असंध और मुनक ब्लॉक के सभी सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन देते किसान। (छाया: एसबी)

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असंध। भारतीय किसान यूनियन ने हल्का प्रधान जोगिंद्र झींडा के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर एसडीएम असंध को ज्ञापन सौंपा। जोगिंद्र झींडा ने कहा कि असंध विस्तार मंडी में कोई चारदीवारी नहीं है। जिससे जमींदारों की फसल चोरी होती है। मंडी के अंदर ना तो पीने के पानी की सुविधा है और ना ही बिजली व बाथरूम की सुविधा है। उन्होंने कहा कि विस्तार मंडी का बाहर आने जाने के लिए कोई गेट नहीं है जिस कारण जाम की स्थिति बन जाती है। झींडा ने कहा कि धान की खरीद जल्दी शुरू करवाई जाए और मंडी में डिजिटल कांटे लगवाए जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

इस अवसर पर कश्मीर सिंह दनौली, दलबीर सिंह रत्तक, वचित्र सिंह, प्रताप सिंह, महेंद्र सिंह, गुरमुख सिंह, बलविंद्र सिंह, संदीप सिंह आदि मौजूद रहे।

राजौंद बाजार में बेसहारा गोवंश से दुकानदार परेशान

■ मार्केट यूनियन ने उठाई समस्या, नपा सचिव ने दिलाया समाधान का आश्वासन

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। नगर के मुख्य बाजार में बेसहारा गोवंश दुकानदारों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। आए दिन बाजार में घूमने वाले गोवंश दुकानों के आगे रखा सामान खा जाते हैं और कपड़े की दुकानों में लटकाए गए कपड़ों को भी चबा जाते हैं। मेन बाजार के बीचोंबीच बैठ जाते हैं। इस कारण दुकानदारों, राहगीरों को परेशानी व आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और बाजार में आने वाले ग्राहकों को भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं।

इस समस्या को लेकर मेन बाजार मार्केट यूनियन प्रधान भीम सिंह राणा और महाराणा प्रताप चौक मार्केट यूनियन प्रधान सन्नी शर्मा ने नगर पालिका सचिव नरेंद्र शर्मा से मुलाकात की और जल्द से जल्द समाधान करने की मांग रखी। यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि यदि स्थिति पर शीघ्र काबू नहीं पाया गया तो दुकानदारों का व्यापार प्रभावित होगा और ग्राहकों का बाजार में आना-जाना भी कम हो सकता है। नपा सचिव नरेंद्र शर्मा ने दुकानदारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा। उन्होंने सफाई निरीक्षक प्रदीप कुमार को निर्देश दिए कि बेसहारा गोवंश को पकड़कर गौशाला में छोड़ा जाए, ताकि बाजार की स्थिति सामान्य हो सके और दुकानदारों को राहत मिल सके।

दुकानदारों ने प्रशासन से अपेक्षा जताई है कि समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि भविष्य में बाजार की गतिविधियां सुचारु रूप से चलती रहें। नगरवासियों का कहना है कि यदि बेसहारा गोवंश को व्यवस्थित तरीके से गौशालाओं में भेजा जाए तो न केवल दुकानदारों को राहत मिलेगी बल्कि सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी।

पर्यावरण, वन प्राणी मंत्री राव नरबीर सिंह ने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत हिसार में किया पौधारोपण

एसबी संवाददाता/चण्डीगढ़। हरियाणा के पर्यावरण, वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कागजी निमंत्रण पत्रों की जगह डिजिटल कार्ड के जरिए निमंत्रण भेजना चाहिए। ऐसा करके हम सभी हर वर्ष बड़ी संख्या में पेड़ों को कटने से बचा कर आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ जीवन की सौगात दे सकते हैं। राव नरबीर सिंह हिसार स्थित बीड़ में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इसी कड़ी में यहां 1500 पौधे रोपित किए गए तथा प्रचार वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए मानव को खाना-पानी तथा हवा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है लेकिन यह तीनों चीजों ही लगातार प्रदूषित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं।

पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रतियोगिता का किया आयोजन

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असंध। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हिन्द की चादर शहीद गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च बलिदान के 350वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान निबंध लेखन, पेंटिंग, स्लोगन, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें 60 से अधिक छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यालय की उप प्रधानाचार्या अकविन्दर कौर ने विद्यार्थियों को गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं व उनके बलिदान और जीवन पर प्रकाश डाला।

विद्यालय के प्रधानाचार्य पवन कुमार जिंदल ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी ने लोगों को प्रेम, एकता व भाईचारे का संदेश दिया। इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान एवं शिक्षाओं से प्रेरणा दिलाना है। कार्यक्रम के समापन पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में घोषित विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर नंद किशोर, संदीप सोनी, सुनील दत्त, सुरेश कल्याण, मोनिका, सुषमा, नीलम आदि उपस्थित रहे।

समाधान शिविर में आई शिकायतों के निवारण में कैथल जिला प्रदेश में प्रथम

कुल प्राप्त शिकायतों में से मात्र एक प्रतिशत शिकायतें लंबित

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। जिले में आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों में आई शिकायतों के निवारण में कैथल जिला हरियाणा में नंबर वन जिला बना है। कुल प्राप्त शिकायतों में से मात्र एक प्रतिशत ही शिकायतें लंबित हैं। जिनके निवारण लिए अधिकारी लगे हुए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से आयुक्त एवं सचिव अमित कुमार अग्रवाल ने पूरे प्रदेश की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में डीसी प्रीति सहित पूरे जिला प्रशासन की सराहना की।

डीसी प्रीति ने समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों के त्वरित समाधान एवं प्रदेश में सबसे कम पेंडेंसी होने का श्रेय जिला की पूरी प्रशासनिक टीम को दिया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आपसी तालमेल के साथ ओर अधिक मेहनत करें। बेहतर परफॉर्मेंस के स्टेटस को बरकरार रखें। समाधान शिविरों में आई शिकायतों का तुरंत समाधान करके गुणवत्तापूर्वक एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) अपलोड करें।

डीसी प्रीति ने बताया कि जिले में अब तक कुल 5093 शिकायतें समाधान शिविरों में प्राप्त हुई हैं, इसमें से 4690 शिकायतों का संबंधित विभागों द्वारा समाधान कर दिया गया है। वहीं 358 शिकायतें तकनीकी कारणों जैसे कोर्ट केस या नोट फिजिबिलिटी के कारण रिजेक्ट हुई हैं। इस समय कुल 45 शिकायतें पेंडिंग है, जिनका संबंधित विभाग जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी इसे अपना सौभाग्य समझें कि ईश्वर ने आपको समाज सेवा का मौका दिया है। हर एक फरियादी समाधान शिविर या आपके कार्यालय में एक उम्मीद लेकर आता है, उसकी शिकायत का निवारण कर आमजन की उम्मीद पर खरा उतरें। जिन भी विभागों की शिकायत पेंडिंग है, वो प्रमुखता के साथ उनका निवारण करें।

इसके अलावा डीसी प्रीति ने जन संवाद, सीएम विंडो तथा एसएमजीटी पर आने वाले शिकायतों की भी विभाग अनुसार समीक्षा की और इन शिकायतों को जल्द निपटाने को लेकर संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला नगर आयुक्त कपिल कुमार, जिला परिषद सीईओ सुरेश रविश, एचएसवीपी ईओ वकील अहमद, एसडीएम अजय सिंह, सीटीएम गुरविंद्र सिंह, डीएसपी बीरभान, डीआरओ चंद्रमोहन, डीडीपीओ रितु लाठर सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

पुलिस अधिकारियों को सामुदायिक सहभागिता मजबूत करने और जन शिकायतों का समाधान करने के निर्देश

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जन संपर्क प्रयासों को तेज करें तथा नागरिक शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावी कानून प्रवर्तन की नींव जनता के विश्वास पर टिकी है। उन्होंने कहा कि कमिश्नर से लेकर डीएसपी तक, हर पुलिस अधिकारी को नागरिकों की चिंताओं से गहराई से जुड़े रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के साथ अधिक संपर्क से नशीली दवाओं के दुरुपयोग और आपराधिक गतिविधियों जैसे मुद्दों से निपटने में मदद मिलेगी। सामुदायिक उपस्थिति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निवासियों के साथ खुला संवाद बनाए रखना और उनकी समस्याओं को सक्रियता से सुनना पुलिस कर्मियों की मुख्य जिम्मेदारी है। उन्होंने नागरिक-अनुकूल पुलिसिंग मॉडल अपनाने का आह्वान किया, जहां त्वरित शिकायत निवारण राज्य में कानून प्रवर्तन कार्यों की रीढ़ बने।

प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने पुलिस आयुक्तों, महानिरीक्षकों, डीसीपी, पुलिस अधीक्षकों और सहायक आयुक्तों/पुलिस उपाधीक्षकों सहित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निदेशों में अधिकारियों को स्थानीय समुदायों के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करने के लिए गांवों में अनिवार्य रात्रि प्रवास सहित नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करने का आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य सरकारी विभागों से संबंधित किसी भी शिकायत को त्वरित समाधान के लिए उपायुक्तों या संबंधित प्राधिकारियों को तुरंत भेजा जाना चाहिए। अधिकारियों को स्थापित मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) एप्लिकेशन के माध्यम से विस्तृत रात्रि विश्राम रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।

नागरिक-पुलिस संपर्क को औपचारिक बनाने के लिए सभी अधिकारियों को सार्वजनिक बैठकों के लिए निश्चित कार्यालय समय निर्धारित करना होगा। उन्हें शिकायतें सुनने और उनका पारदर्शी तरीके से समाधान करने के लिए कार्य दिवसों में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक अपने कार्यालयों में उपलब्ध रहना होगा। उन्होंने बताया कि निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया गया है।